कारीगरों और शिल्पकारों को नये अवसर दे रही है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना : दिया कुमारी

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की प्रथम वर्षगांठ पर कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार द्वारा शुक्रवार को वर्धा, महाराष्ट्र में आयोजित कार्यक्रम से आईटीआई जयपुर से योजना अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थी वर्चुअली जुड़े।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य में उक्त कार्यक्रम जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। दिया कुमारी ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि हुनरमंद कलाकार लोग एक साल पहले यह सोच भी नहीं सकते थे कि उनके उत्थान के बारे में कोई सोचता है। किन्तु दूरदृष्टि और संवेदनशीलता के धनी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने शानदार विजन के अनुसार आज से एक साल पहले ऐसे हाथ से काम करने वाले कारीगरों और कलाकारों के लिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को शुरू किया।

दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन अनुसार इस योजना की शानदार सफलता का एक साल पूरा होना गर्व का विषय है। 18 पारम्परिक कलाओं से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। यह समारोह इस योजना की सफलता की कहानी बता रहा है। हाथ के कारीगरों, हुनरमंद कलाकारों के लिए योजना वरदान साबित हो रही है। छोटे स्तर पर काम करने वाले इन कारीगरों एवं शिल्पकारों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए आसानी से ऋण मिल रहा है, कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और टूलकिट खरीदने के लिए ई-वाउचर दिए जा रहे है।

उन्होंने ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच "हुनर से होगा देश का नवनिर्माण" इस योजना के माध्यम से साकार हो रही है। यह एक ऐसी योजना है जिससे हुनरमंद हाथ के कारीगरों को, कलाकारों को एक बार ही नहीं अपितु बार-बार लाभ होगा। प्रधानमंत्री "वोकल फोर लोकल" की सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हुनर मंद लोगों को योजना की जानकारी दी जाए, ताकि वो इस योजना से जुड़कर लाभ उठा सकें और आगे बढ़ सकें। योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। दिया कुमारी ने कहा कि मुझे खुशी है कि इस योजना से पुरुष कारीगर लोगों के साथ ही महिला कारीगर भी जुड़ रही है। उन्होंने कहा कि आज आरआईसी परिसर में आयोजित प्रदर्शनी में मुझे महिला कारीगरों और हस्त शिल्पियों की संख्या ज्यादा दिखी है। यह इस योजना से महिला उत्थान का भी एक अच्छा उदाहरण है। योजना से महिला कलाकारों को भी लाभ हो रहा है, वे आगे बढ़ रही हैं यह बहुत शानदार और प्रसन्नता की बात है। इस अवसर पर जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा ने अपने सम्बोधन में कहा कि कारीगरों और शिल्पकारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य विरासत भी विकास भी है। सांसद ने कहा कि माल बनाने में मदद करने के बाद उस माल को बेचने का अवसर दिया जा रहा है। डिजिटल पेमेंट किया जाता है। समाज में आसपास वालों को इस योजना से जुड़ने के लिए, योजना की जानकारी दी जावें। उन्होंने कहा कि इस योजना खुद जाने और दूसरों को इसकी जानकारी देवें। उन्होंने कहा कि हुनर से होगा देश का नवनिर्माण।

इस अवसर पर कारीगरों और शिल्पियों को एक लाख रूपये के ऋण के चेक वितरित किये गए।

इससे पूर्व उपमुख्यमंत्री, सांसद एवं विधायक तथा अन्य व्यक्तियों के आगमन के पश्चात उनका अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि दिया कुमारी द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया।

वर्धा से पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग हुई। विश्वकर्माओं को कौशल प्रमाण पत्र एवं अन्य लाभ वितरित किये गये। विश्वकर्मा लाभार्थियों का समूह फोटो लिया गया।

इस अवसर पर आयुक्त कौशल, रोजगार और उद्यिमता विभाग, राजस्थान सरकार हृदेश कुमार शर्मा, एस.एस. नायक, एन.के. गुप्ता अध्यक्ष विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड एवं अन्य जन प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, साथ ही कार्यक्रम में विश्वकर्मा योजना के लगभग 200 प्रशिक्षु/लाभार्थी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में विश्वकर्माओं को कौशल प्रमाण पत्र एवं अन्य लाभ वितरित किये।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री कार्यालय में शुक्रवार को दक्षिण-पश्चिमी कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिन्दर सिंह ने मुलाकात की। शर्मा से लेफ्टिनेंट जनरल सिंह की यह शिष्टाचार भेंट थी।

भजनलाल शर्मा से ब्रिटिश उप उच्चायुक्त ने की मुलाकात

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री कार्यालय में शुक्रवार को ब्रिटिश उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग ने मुलाकात की। इस दौरान शर्मा ने हिकलिंग से आगामी 9 से 11 दिसंबर तक राजस्थान में आयोजित होने वाले 'राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमैंट समिट' में ब्रिटिश निवेशकों की सहभागिता पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में निवेश के अवसरों, आर्थिक विकास की संभावनाओं तथा प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों के बारे में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त के साथ जानकारी साझा की।

- 'राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमैंट समिट' में ब्रिटिश निवेशकों की सहभागिता पर चर्चा

हिकलिंग ने मुख्यमंत्री को सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान को देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश उप उच्चायुक्त को 'राइजिंग राजस्थान किट' भेंट की। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

नाहरगढ़ की पहाडियों से लापता हुए युवक की तलाश के प्रयासों की दी जानकारी

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से नाहरगढ़ की पहाडियों से गत 1 सितंबर को लापता हुए राहुल की तलाश के प्रयासों की जानकारी दी। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पेश स्टेट्स रिपोर्ट पर संतोष जताते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद रखी है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश लापता युवक के पिता सुरेश चंद्र शर्मा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिए।

सुनवाई के दौरान डीसीपी राशि डोगरा और एसीपी बजरंग सिंह सहित अन्य स्थानीय पुलिस अधिकारी पेश हुए। इस दौरान पुलिस की ओर से अदालत को लापता की तलाश में उठाए गए कदमों की रोजाना के आधार पर रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया की शुरुआत में करीब तीन सौ लोगों की सहायता से राहुल की तलाश की गई। वहीं बाद में ड्रोन, डॉग स्क्वायड की भी सहायता ली गई, लेकिन उसका पता नहीं चला। मामले में गंभीरता दिखाते हुए एसआईटी का गठन भी किया गया। वहीं वेदांता कंपनी से आए प्रशिक्षित लोगों ने भी अत्याधुनिक मशीन से उसकी तलाश की। इसके अलावा लापता की जानकारी बताने पर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया।

पुलिस की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि युवक की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर भी लगाया गया। वहीं नाहरगढ़ की पहाडियों, गहरी खाइयों, पहाड़ी से नीचे की जाने वाले रास्तों और आसपास के क्षेत्र में भी तलाश की गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वर्तमान में सभी तकनीकी संसाधनों से संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है। इस पर अदालत ने तलाश जारी रखते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है।

अधिवक्ता गिर्राज शर्मा ने बताया कि राहुल अपने भाई आशीष के साथ 1 सितंबर को तरण मंदिर घूमने की कहकर घर से निकला था। अगले दिन पुलिस को आशीष का शव पहाडियों पर मिला और राहुल अभी तक लापता चला है। वहीं उनके पिता ने राहुल को किसी की कैद में होने का अंदेशा जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

वृत्त कार्यालयों में बनाएं हैल्प डेस्क

जयपुर। डिस्कॉम्स चेयरमैन एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने आमजन व बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए जयपुर शहर एवं जयपुर जिला वृत्त के अधीक्षण अभियंता कार्यालयों में हैल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन हैल्प डेस्क के माध्यम से बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आमजन को पूरी संवेदनशीलता से परामर्श प्रदान किया जाए। डोगरा शुक्रवार को विद्युत भवन में जयपुर सिटी एवं जयपुर जिला सर्किल के वृत्त अधीक्षण अभियंताओं के साथ इस संबंध में समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में अपनी समस्याओं तथा सुनवाई को लेकर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं।

मेयर मुनेश गुर्जर की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध

जयपुर। रिश्वत लेकर पट्टे जारी करने के मामले में एसीबी की ओर से गत वर्ष 6 अगस्त को दर्ज एफआईआर को हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर ने हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका दायर कर चुनौती दी है। याचिका पर जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ शनिवार को सुनवाई करेगी। याचिका में राज्य सरकार और मामले के शिकायतकर्ता सुधांशु सिंह को पक्षकार बनाकर गुहार की गई है कि एसीबी की इस एफआईआर को रद्द किया जाए। याचिका में अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि इस मामले में एसीबी याचिकाकर्ता से कोई भी डिमांड साबित करने में विफल रही है। एसीबी ने यह नहीं बताया है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से कैसे डिमांड की और एसीबी ने उसका सत्यापन कैसे किया। इसके अलावा याचिकाकर्ता से कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। वहीं मामले में दर्ज एफआईआर में याचिकाकर्ता की भूमिका होने के संबंध में कोई भी सबूत नहीं है। ऐसे में एसीबी की एफआईआर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जरूरी शर्तों डिमांड व रिकवरी को ही सत्यापित नहीं करती है। इस संबंध में पूर्व में उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं पाए थे, यदि साक्ष्य होते तो उसके खिलाफ उसी समय कार्रवाई हो जाती। याचिकाकर्ता को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और एफआईआर दुर्भावना के चलते दर्ज करवाई है। गौरतलब है कि एसीबी ने मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को नगर निगम से पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत मांगने से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने मुनेश को निलंबित कर दिया था। इस निलंबन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।

वहीं बाद में सरकार ने निलंबन आदेश वापस ले लिया था। राज्य सरकार ने जांच के बाद मुनेश को पुनः निलंबित किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने दिसंबर, 2023 में निलंबन को रद्द कर दिया था। वहीं गत दिनों एसीबी ने अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद मुनेश और उसके पति सुशील सहित दो अन्य के खिलाफ एसीबी कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया है।

'डोटासरा ना भूले मर्यादा, भाजपा का जबाव भारी पड़ेगा'

जयपुर। भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के भाजपा नेताओं के राजस्थान में प्रवेश को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने जवाब देना शुरू किया तो कांग्रेसी नेताओं को मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की आदत बनती जा रही है कि बेवजह की बयानबाजी करो और फिर माहौल खराब करो और अपने आलाकमान को खुश करो ताकि कुर्सी बची रहे। उन्होंने कहा कि गोविंद डोटासरा ने जिन केंद्रीय मंत्री के खिलाफ बयान दिया है उनके दादाजी बेअंत सिंह की शहादत को भूल कर केवल गांधी परिवार की चापलूसी के लिए बयान वीर बनते है। गोठवाल ने कहा कि राजस्थान अपनी समृद्ध राजनीतिक परंपरा के लिए जाना जाता है परंतु ऐसे लगता है डोटासरा ने जिस तरह कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बनते हुए अपने ही नेता सचिन पायलट की बेकद्री की थी उसका मानसिक असर अब भी है।

कर्मचारियों की वरिष्ठता मेरिट के बजाए नियुक्ति तिथि से तय करने पर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ही भर्ती में विभिन्न जिलों में नियुक्त विलेज लेवल ऑफिसरों की वरिष्ठता मेरिट के बजाए उनकी नियुक्ति तिथि और स्थायीकरण से करने से जुड़े मामले में प्रमुख पंचायती राज सचिव, पंचायती राज निदेशक और धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से जवाब तलब किया है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश जितेंद्र सिंह की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता हरेंद्र नील ने बताया कि वर्ष 1999 में जिलेवार विलेज लेवल ऑफिसर भर्ती निकाली गई थी। जिसकी लिखित परीक्षा एक समान प्रश्न पत्र के जरिए ही एक समय पर आयोजित की गई थी। वहीं संबंधित जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर अलग-अलग समय पर चयनितों को इस पद पर नियुक्ति दी। जिसके तहत याचिकाकर्ता धौलपुर जिले में नियुक्त हुआ। याचिका में कहा गया कि पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 285 के तहत विलेज लेवल ऑफिसर पद की वरिष्ठता सूची संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति व स्थाईकरण की तिथि से करना तय किया गया। याचिका में इस प्रावधान को चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता के प्रकरण में सभी अभ्यर्थियों की भर्ती एक समय पर और एक समान प्रश्न पत्र के जरिए हुई थी। हालांकि प्रशासनिक कारणों के कारण कई जिलों ने सफल अभ्यर्थियों को देरी से नियुक्ति दी।

राज्य कर्मचारियों ने मनाया ज्ञापन दिवस

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक में राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को लेकर की गई घोषणा की क्रियान्विति नहीं होने के विरोध में शुक्रवार को हजारों राज्य कर्मचारियों ने अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के आव्हान पर पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिवस मनाया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन प्रस्तुत किया। राजधानी जयपुर में यह ज्ञापन महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ व जिला अध्यक्ष छोटेलाल मीणा की अगुवाई में गए एक शिष्ट मंडल ने मुख्य सचिव को सौंपा।

नियुक्ति पत्र जारी क्यों नहीं किए?

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी टीचर्स को नियुक्ति के बाद में भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने को गंभीरता से लिया है। अदालत ने कहा है ऐसे कई मामले आ रहे हैं, जिनमें नियुक्ति के बाद गेस्ट फैकल्टी टीचर्स को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए है।

वहीं मामले में सरकारी वकील भी अदालत को इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में कॉलेज शिक्षा आयुक्त 27 सितंबर तक शपथ पत्र दायर कर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पेश करें।

बी.एस.एन.एल. में 'नैतिकता-शासन' सेमीनार

जयपुर। राजस्थान बी.एस.एन.एल. परिमंडल की विजिलेंस सेल ने शुक्रवार को कार्यालय प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार जयपुर के कॉफ्रेंस हॉल में नैतिकता एवं शासन सेमीनार आयोजित किया। महाप्रबंधक (सतर्कता) दिनेश कुमार गर्ग ने सभी अधिकारियों, अतिथियों तथा प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह एवं आयोजित होने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में बताया। सेमीनार का उद्घाटन बीएसएनएल राजस्थान परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक विक्रम मालवीय ने किया। सेमीनार के मुख्य अतिथि एवं वक्ता पूर्व आईएएस अधिकारी एस.एस.बिस्सा थे। बीएसएनएल राजस्थान परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक विक्रम मालवीय ने अपने उदबोधन में नैतिक मूल्यों के साथ जीवन जीने पर प्रकाश डाला तथा तथा उत्तम व्यवहार एवं सदाचार को जीवन में अपनाने के लिए कहा। साथ ही, प्रशासन में पारदर्शिता अपनाने पर भी बल दिया। मुख्य अतिथि एवं वक्ता पूर्व आईएएस अधिकारी एस.एस.बिस्सा ने अपने व्याख्यान की शुरुआत ऋग्वेद के एक श्लोक से की।

3.15 करोड़ की नई सड़क बनाने से पहले लाखों का फर्जी भुगतान उठाने के लिए करवाए घटिया पेचवर्क?

अजमेर एलिवेटेड रोड पर बुधवार रात को जेडीए जोन-7 द्वारा कराए गए पेचवर्क एक रात भी नहीं टिके

अजमेर एलिवेटेड रोड पर पेचवर्क उखड़ने के बाद सड़क पर बिखरी रोड़ी-कंक्रीट, जो हादसों को न्यौता दे रही है।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। अजमेर एलिवेटेड रोड पर घटिया पेचवर्क और दुगुने पैसे लगाकर उसे उखाड़ने में जे.डी.ए. के लाखों रुपए की बर्बादी करने के मामले में जे.डी.ए. कमिश्नर आनंदी ने वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मांग ली। मजेदार बात यह है कि जेडीए जोन-7 ने अजमेर रोड एलीवेटेड रोड पर पुरानी चुंगी से मजार तक 3.15 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क बनाने के लिए टेंडर जारी किया है। यानि कि 3.15 करोड़ रुपए लगाकर सड़क की रि-कारपेटिंग की जायेगी। टेंडर की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर है। सफल आवेदक को वर्क आर्डर जारी किया जाएगा। इस कारपेटिंग से पहले सड़क पर पुरानी डामर को उखाड़ा जाएगा। ऐसे में यह सभी पेचवर्क भी उखड़ेंगे, जो बरसात के दौरान किये जा रहे हैं।

सूत्रों की मानें तो नई सड़क निर्माण से पहले जेडीए जोन-7 के इंजीनियर्स ने बुधवार रात आनन-फानन में यह घटिया पेचवर्क कराए, जो कुछ घंटे भी नहीं चले। यह कारनामा ठेकेदार व इंजीनियर्स ने इसलिए किया गया कि, कुछ दिनों बाद जब सड़क नई बनाई जाये, तब यह पेचवर्क उखाड़ने पड़ेंगे, ऐसे में चुपचाप लाखों रु. का भुगतान उठा लिया जाये।

- यह मामला उजागर होने के बाद शुक्रवार को जे.डी.ए. कमिश्नर ने अतिरिक्त निदेशक से रिपोर्ट मांगी
- अजमेर रोड एलीवेटेड रोड पर पुरानी चुंगी से मजार तक सड़क निर्माण के लिए गत दिनों जारी किया है करीब 3.15 करोड़ रु. का टेंडर

'राष्ट्रदूत' में घटिया पेचवर्क की खबर छपने के बाद शुक्रवार को जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने अतिरिक्त निदेशक संजीव जैन से इस मामले में वस्तुस्थिति से अवगत कराने और वास्तविक रिपोर्ट देने को कहा। घटिया पेचवर्क करने का मामला उजागर होते ही जोन 7 के एक्सईएन तरुण सिंघल ने अपनी अलग-अलग टीमें मामले को मैनेज करने में लगा दी।

इस बीच मामला बिगड़ता देख एक्सईएन सिंघल ने घटिया पेचवर्क के काम को छिपाने के लिए ठेकेदार खुदाबक्स से मौके पर झाड़ू लगवाने को कहा, ताकि रोड पर बिखरी रोड़ी-कंक्रीट नहीं दिखे।

एक करोड़ रुपए के पेचवर्क पानी में बहे

सूत्रों की मानें तो जोन-7 में मार्च माह में ही एक करोड़ रुपए पेचवर्क कराने के लिए स्वीकृत करते हुए टेंडर जारी कर दिए थे। यह टेंडर खुदाबक्स कंपनी ने हासिल किए। इसके बाद बरसात और उससे पहले ठेकेदार को पेचवर्क करने का वर्क आर्डर अगस्त तक जारी नहीं किया। सितंबर माह में अचानक जेडीए के जोन 7 के इंजीनियर्स को ध्यान आया कि इस एलीवेटेड रोड पर पेचवर्क कराया जाए। इसके बाद एक रात में ऐसे घटिया पेचवर्क कराए कि अगले दिन सवेरे ही बिखर गए। मामला बिगड़ता देख शुक्रवार को इन उखड़े हुए पेचवर्क पर कोल्ड डामर कराई गई, जिससे यह टाट के पैबंद जैसी यह लग रही थी। अब ठेकेदार को घटिया पेचवर्क का भुगतान करने की तैयारी की जा रही है।

सूत्रों की मानें तो जोन 7 के इंजीनियर्स को जेडीए प्रशासन की सख्ती और कार्रवाई का भी कोई डर नहीं है। ऐसे में वह मौके पर जाकर पेचवर्क करने या सड़क की कारपेटिंग कराने में भी ध्यान नहीं देते। पीछे से ठेकेदार को पूरी छूट मिल जाती है और वह पेचवर्क के नाम से हल्की डामर की परत चढ़ाकर अपने काम की इतिश्री कर लेते हैं।

निदेशक एक माह के अवकाश पर

सूत्रों की मानें तो जेडीए के निदेशक इंजीनियरिंग अजय गर्ग एक महीने के अवकाश पर चले गए हैं। जेडीए में चर्चा है कि नई जेडीए कमिश्नर से उनकी पटरी नहीं बैठ रही है। उनकी नाराजगी से बचने के लिए निदेशक एक महीने के अवकाश पर चले गए। उनका कार्यभार अतिरिक्त चीफ इंजीनियर संजीव जैन को सौंपा गया है।

गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना में प्रदेशभर में लगाए जाएंगे कैंप

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा गौ-पालक परिवारों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर शुरू की गई गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की क्रियान्विति के लिये राज्यभर में अगले सप्ताह से एक पखवाड़े तक कैम्प लगेंगे। योजना में पात्र गोपालकों को एक वर्ष की अवधि के लिये एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। आगामी 25 सितम्बर से 9 अक्टूबर तक की अवधि के दौरान ब्लॉक स्तर पर डेयरी समितियों और केन्द्रीय सहकारी बैंक (पैक्स) के संयुक्त कैम्पों में गोपालकों से ऑनलाईन आवेदन लिये जाएंगे।

- गौ-पालकों को एक वर्ष की अवधि के लिये एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा

यह जानकारी देते हुए राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन की प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में गोपालकों को डेयरी से संबंधित गतिविधियों जैसे गौवंश हेतु शैड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध, चारा, बांट के उपकरण खरीदने के लिये किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट योजना की क्रियान्विति की जा रही है।

प्रथम चरण में 5 लाख गौ-पालक परिवारों को ऋण उपलब्ध कराये जाएंगे, और इस योजना पर आगामी वर्ष 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि गोपालकों को ऋण के लिये ऑनलाईन आवेदन हेतु राज्यभर के जिला दुग्ध संघों को पैक्स बैंक के साथ मिलकर ब्लॉक स्तर पर कैम्प आयोजित करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। एक गोपालक परिवार से एक सदस्य जो कि सहकारी डेयरी समिति को दूध का बेचान करता हो, को प्राथमिक दुग्ध समिति की अनुशंषा पर ऋण प्राप्त कर सकता है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत ऋण हेतु गोपालक से कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जावेगा। गोपालक द्वारा समय पर अथवा समय से पूर्व चुकारा किये जाने पर आगामी एक वर्ष के लिये नवीन ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।